(ग) जिन किसानों की भूमि इस प्रकार अर्जित की जाती है, इनको वैकल्पिक प्लाट के लिए पात्र बनाने हेतु

दिल्ली के गांवों की भूमि का अधिग्रहण

4222. **श्री रशीद मसूद :**
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा हाल ही में दिल्ली के तेरह छोटे गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिग्रहण किये जाने हेतु कितनी भूमि के लिये नोटिस दिया गया था उसमें से कितनी भूमि वास्तव में अधिग्रहीत की गई ; और

(घ) जिस भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिये दक्षिण दिल्ली के 13 गांवों में 54,959 बीघा और एक बिस्वा भूमि को भूम अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिसूचित किया गया था और 42,530 बीघा 16 बिसवा भूमि के लिये अवार्ड की घोषणा मई–जून 1987 में की गई थी। प्रथमतः खाली भूमि का कब्जा लेने की निर्णय लिया गया था।

(ग) अब तक 9 गांवों में लगभग 7000 बीघा भूमि कब्जे में ली गयी है।

(घ) 1207 बीघा 15 बिसवा भूमि छोड़ दी गई थी क्योंकि दिल्ली नगर निगम द्वारा भवन नक्शें 5–11–80 से पूर्व स्वीकृत किये गये थे । छतरपुर मंदिर प्राधिकारियों से संबंधित 87 बीघा 12 बिस्वा भूमि भी अधिसूचना मुक्त कर दी गई थी । 1746 बीघा 6 बिस्वा भूमि दिल्ली उच्च न्याय लय के यथा स्थिति आदेशों के अन्तर्गत शामिल है । इसके अलावा, 3073 बीघा 15 बिस्वा भूमि निर्मित होने के कारण छोड़ दी गई थी कुल 42,530 बीघा 16 बिस्वा भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण अवार्ड मई-जून, 1987 में घोषित किए गये थे । 14833 बीघा 3 बिस्वा भूमि बाद में अधिसूचिना मुक्त कर दी गई थी और वनरोपण के लिए विकास आयुक्त, दिल्ली को दे दी गई थी क्योंकि वह भूमि ग्राम सभाओं से संबंधित थी ।

सरदार सरोवर परियोजना के लिए केन्द्रीय अनुदान

4223. **कुमारी सईदा खातून** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरदार सरोवर परियोजना को दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री जी० एस० ढिल्लों) : (क) और (ख) सरकार सरोवर परियोजना का वित्त-पोषण राज्य सरकारें अपनी योजना धनराशि में से कर रही हैं राज्यों को केन्द्रीय सहायता निर्धारित सिद्धांत के अनुसार समूची योजना के लिए उपलब्ध कराई जाती है । अनुदान में वृद्धि करने का कोई प्रस्तावित नहीं है

Allotment of quarters to Central Government Employees

4224. SHRI M. KADHARSHA:
SHRI F. M. KHAN:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state

(a) what is the allotment year at present under which Central Government quarters

in Delhi are being allotted for categories A, B, C, D and E;

(b) whether Government propose to invite applications for allotment of quarters in Delhi for A, B, C, D and E categories according to the pay fixed on the basis of Fourth Pay Commission; and

(c) if so, upto which year of allotment and by when the applications are proposed to be invited?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Initially the present allotment year was from 1st April, 1985 to 31st March, 1987. This was extended upto the end of September, 1987 and is proposed to be extended upto the end of December, 1987.

(b) Yes, Sir.

(c) The next allotment year is expected to commence from 1-1-1988 and will remain in force for a period of 2 years. Applications are proposed to be invited during August-September, 1987.

Shops and establishments reserved by NDMC forest

4225. SHRI S. C. JAMIR:
SHRI DHULESHWAR MEENA:
SHRI PRITHIBI MAJHI:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the New Delhi Municipal Committee has not been able to allot various categories of shops and establishments for the last forty years which had been reserved for the Scheduled Tribes;

(b) whether Government are aware of the facts that the requisite percentage of shops and establishments have not been allocated under the declared policy of the Government by the New Delhi Municipal Committee; and

(c) whether in view of the large number of immigrants belonging to Scheduled Tribes from all over the country what steps the New Delhi Municipal Committee propose to take with regard to the Scheduled Tribes' ingress?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) The N.D.M.C. have informed that the Government orders regarding reservation of shops of various categories have already been followed by the Committee. The allotment of shops|kiosks in the shopping complexes of the N.D.M.C. is being made on Tender basis which are open to all. However, 12.8 per cent of shops|kiosks, as per the guidelines issued by the Government, are reserved for SC|ST which are allotted by the N.D.M.C. at the reserved rate to the applicants by draw of lots.

Central assistance to Maharashtra for drinking water

4226. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the amount of Central assistance reuqested by the Government of Maharashtra for drinking water supply and when;

(b) what was the amount sanctioned and when;

(c) what are the guidelines followed by Government in sanctioning such assistance;

(d) whether Government of Maharashtra's request fulfilled the guidelines; and

(e) if so, whether a meagre assistance was given and if not what were the guidelines now followed by the Government of Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) and (b) No specific request has been received from the Government of Maharashtra for Central assistance for drinking water supply. However,